मेसर्स अशोक लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

रमेश कुमार- प्रतिवादी

सी.आर.एल. 2001 का आर नंबर 486

9 मई, 2002

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 451-मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 41 और 230-किराया खरीद समझौता-किराएदार द्वारा किश्तों के भुगतान में चूक-चाहे कंपनी/
फाइनेंसर को वाहन का कब्ज़ा लेने का अधिकार है - माना जाता है, हाँ - उसके नाम पर जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र किराएदार को पूर्ण मालिक बनने का कोई अधिकार नहीं देता है जब तक कि वह किराया खरीद समझौते के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करता है - जिला न्यायाधीश के आदेश जिसमें किराएदार के पक्ष में वाहन को जारी करने का निर्देश दिया गया उसको ख़ारिज करते हुए इस याचिका को दायर किया गया
माना गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों का शुद्ध परिणाम यह होगा कि किराया खरीद समझौता होने के बावजूद, किराया-खरीद समझौते के तहत कब्जा रखने वाला व्यक्ति धारा 41 के तहत एक आवेदन दायर करने का हकदार होगा जिससे वह पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकृत स्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में सक्षम हो सके।1988 के अधिनियम के तहत इन प्रावधानों को सक्षम करने का उद्देश्य किराएदार को मालिक के रूप में मान्यता देना है, जिससे न केवल वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र बरकरार रखा जा सके, जो कि किराया खरीद समझौते का विषय है, बल्कि उसे फिटनेस सर्टिफ़िकेट प्राप्त करने में भी मदद करना है। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वाहन का बीमा रूट परमिट आदि कराना आवश्यक है जिसका अनुपालन 1988 अधिनियम के तहत किया जाना आवश्यक है ताकि वाहन को किसी भी ओर से बिना किसी बाधा के चलाया जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूर्ण मालिक बन जाता है क्योंकि किराया खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार, किराएदार को उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा और किस्तों की राशि का भुगतान करना होगा ताकि वह पूर्ण मालिक बन सके। किराया खरीद समझौता.

(पैरा 15)

इसके अलावा, यह माना गया कि चूंकि वाहन की हिरासत का दावा किराएदार और फाइनेंसर-याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था, मजिस्ट्रेट किराया खरीद समझौते की शर्तों की जांच करने के लिए बाध्य था ।क्योंकि फाइनेंसर द्वारा एक निश्चित स्टैंड लिया गया था कि किरायेदार द्वारा किस राशि का भुगतान नहीं किया गया और केवल इसलिए कि पंजीकरण प्रमाणपत्र किराएदार के नाम पर जारी किया गया है, जो वैसे उस वाहन का हक़दार नहीं बनता लेकिन किराया ख़रीद समझौते की वजह से वह हक़दार बना वह किसी भी तरीके से किराया-खरीद समझौते के तहत फाइनेंसर के वाहन की अंतरिम हिरासत प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया जाएगा क्योंकि उस समय तक किराएदार संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं बन गया था।

विर्क, याचिकाकर्ता के वकील

जे.एस. यादव, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

आर.सी. कथूरिया, जे

(1) याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 2000 की वैधता को चुनौती देते हुए वर्तमान पुनरीक्षण दायर किया है, जिसके तहत उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी द्वारा दिनांक 7 जून, 2000 को आदेश दिया गया था जिसमें वाहन पंजीकरण संख्या एचआर-34/7486 वाली जीप की मैसर्स को सुपरडारी पर
अशोक लीलैंड, हिसार (यहां याचिकाकर्ता) को दिया गया और सत्र न्यायाधीश द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया गया और वाहन को प्रतिवादी रमेश कुमार को सुपरदारी पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

2) वर्तमान याचिका में उठाए गए विवाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) रमेश कुमार (यहां प्रतिवादी) ने 27 फरवरी, 1998 को याचिकाकर्ता के साथ किराया-खरीद समझौता किया है ताकि पंजीकरण संख्या एचआर-34/7486 वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप की खरीद के लिए वित्त सुविधा का लाभ उठाया जा सके। जीप की कुल चालान कीमत रु. 3,06,000, रुपये की राशि. याचिकाकर्ता द्वारा प्रति वर्ष 12.92 प्रतिशत फ्लैट दर पर 2,00,000 रुपये का वित्त पोषण किया गया था, जिसे 27 फरवरी, 1998 से शुरू होकर 27 दिसंबर, 1999 तक 23 किराया धन किश्तों में चुकाना था। प्रतिवादी अतिरिक्त वित्त शुल्क का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुआ था। अंतिम भुगतान तक किसी भी किस्त का भुगतान करने में चूक की स्थिति में 36 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर। 27 फरवरी, 1998 (अनुबंध पी-1) के समझौते के तहत, याचिकाकर्ता को मालिक और प्रतिवादी को किरायेदार कहा गया था। समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि यदि प्रतिवादी द्वारा समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया, तो याचिकाकर्ता वाहन का कब्ज़ा लेने का हकदार होगा। प्रतिवादी ने रुपये की किश्तों के भुगतान की अनुसूची का पालन नहीं किया। 27 अक्टूबर, 2000 को निपटाए गए खातों के अनुसार 1,08,122 रुपये देय और बकाया हो गए। प्रतिवादी द्वारा किश्तों के भुगतान में चूक के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने 19 मई, 2000 को छोटू राम को वाहन का कब्जा लेने के लिए अधिकृत किया। कार्यालय पत्र दिनांक 19 मई, 2000 के अनुसार प्रतिवादी से। उक्त वाहन को पुलिस ने धारा 323/506/341/500/506/ के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 101 दिनांक 25 फरवरी, 2002 वाले एक आपराधिक मामले में कब्जे में ले लिया था। 147/149आईपीसी पुलिस थाना बाढड़ा, जिला भिवानी में। याचिकाकर्ता के रुख के अनुसार, इस एफआईआर में हेराफेरी की गई और प्रतिवादी द्वारा वाहन को दोबारा कब्जे में लेने से रोकने के लिए इसे दर्ज कराया गया। याचिकाकर्ता ने सुपरदारी पर विचाराधीन वाहन को रिलीज करने के लिए आवेदन किया था और उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 जून, 2000 के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और याचिकाकर्ता के आवश्यक ज़मानत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर वाहन को रिलीज करने का आदेश दिया गया था ।उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 7 जून, 2000 के आदेश को प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने 23 दिसंबर, 2000 के आदेश और 7 जून, 2000 के आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया था। उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी के आदेश को रद्द कर दिया गया और विचाराधीन वाहन को प्रतिवादी ओह सुपरडारी को जारी करने का निर्देश दिया गया था। इन परिस्थितियों में, सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा पारित 23 दिसंबर 2000 के आदेश को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई है।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि 27 फरवरी, 1998 के समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता वाहन का मालिक बना रहेगा क्योंकि प्रतिवादी ने किराया राशि की किश्तों और एक राशि के भुगतान में चूक की है। रुपये का 27 अक्टूबर, 2000 को निपटाए गए खातों के अनुसार उनके खिलाफ 1,08,122 रुपये बकाया थे और इस कारण से, सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन के फाइनेंसर और मालिक होने के नाते याचिकाकर्ता के पक्ष में वाहन जारी करने का सही आदेश दिया था। . अपनाए गए रुख के समर्थन में, सरदार त्रिलोक सिंह और अन्य बनाम सत्य देव त्रिपाठी (1) और मैन पाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम टी. बंगारप्पा और अन्य, (2) के फैसलों पर भरोसा किया गया।

(6) प्रस्तुत प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, प्रतिवादी के वकील ने सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा पारित 23 दिसंबर, 2000 के आदेश को उसमें बताए गए कारणों से उचित ठहराया है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य (3) मामले के फैसले पर भी भरोसा जताया है।

(7) उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी द्वारा याचिकाकर्ता को सुपरदारी पर विचाराधीन वाहन को छोड़ने के लिए जो कारण प्रचलित थे, वे उनके आदेश दिनांक 7 जून, 2000 के पैरा 4 और 5 में निहित हैं। की ओर से लिया गया रुख प्रतिवादी ने कहा कि वह प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी था, इसे स्वीकार नहीं किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 2000 के पैरा 11 में निहित कारणों से उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के दिनांक 7 जून, 2000 के आदेश को रद्द कर दिया, जो इस प्रकार है: -

"11. मामले के व्यापक तथ्य यह है कि रमेश कुमार, जिसने प्रतिवादी नंबर 1 अशोक लीलैंड से ऋण प्राप्त किया था, जीप नंबर एचआर-34/7486 का पंजीकृत मालिक है। कुछ किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई कुल किश्तों का कोई विवरण नहीं है। प्रश्नगत जीप को एफआईआर संख्या 101, दिनांक 25 मई, 2000 के मामले में याचिकाकर्ता से और उसके बाद फाइनेंसर, यानी प्रतिवादी संख्या 1, उप-विभागीय द्वारा दिए गए एक आवेदन पर कब्जे में ले लिया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए आदेश दिया कि सुपरदारी उस फाइनेंसर को दी जाए जिसके पास प्रश्न में वाहन का सबसे अच्छा स्वामित्व है। निस्संदेह, किस्तों का भुगतान न करने की स्थिति में फाइनेंसर, यानी प्रतिवादी नंबर 1 किसी भी उल्लंघन के मामले में शेष राशि की वसूली के लिए संशोधनवादी-याचिकाकर्ता पर मुकदमा कर सकता है। हालाँकि, पर्यवेक्षण पर विचाराधीन वाहन को छोड़ने के वर्तमान आवेदन में उस तथ्य को उजागर नहीं किया जा सका। इसलिए, राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2000(2) न्यायिक रिपोर्ट (आपराधिक) 621 में निर्धारित कानून के मद्देनजर, विवादित आदेश मामले के तथ्यों की सही समझ पर आधारित नहीं है। चूंकि वाहन को पंजीकृत मालिक से कब्जे में लिया गया था, इसलिए, पंजीकृत मालिक जिसने फाइनेंसर कंपनी को कुछ किश्तों का भुगतान किया है, दी गई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को उन्हीं नियमों और शर्तों पर सुपरदारी दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया गया है। विवादित आदेश।"

8) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने विद्वान सत्र न्यायाधीश के उपरोक्त निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए तर्क दिया है कि सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुद्दा यह नहीं था कि पुलिस ने वाहन का कब्ज़ा किससे लिया था; बल्कि संक्षिप्त विवाद का निर्णय यह था कि धारा 451 सीआर के तहत सुपरडारी पर वाहन प्राप्त करने का हकदार कौन था। पी.सी. उनके अनुसार, 27 फरवरी, 1998 के किराया-खरीद समझौते के तहत मालिक होने के नाते याचिकाकर्ता वाहन के कब्जे का

हकदार था। अपने रुख का समर्थन करने के लिए, उन्होंने मणिपाल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहजता (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों से ताकत हासिल की। उपर्युक्त मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता-वित्त कंपनी ने प्रतिवादी नंबर 1 को किराया-खरीद के आधार पर वित्तीय सुविधा दी थी मेटाडोर MEZ-6502 की खरीद के लिए। चूँकि किराये पर लेने वाला किस्तों का भुगतान करने में विफल रहा और लगातार चूक करता रहा, अपीलकर्ता-कंपनी ने किराया-खरीद समझौते की शर्तों के तहत 6 जून, 1987 को वाहन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद, किराएदार ने अपीलकर्ता-कंपनी के उन दो कर्मचारियों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने वाहन जब्त कर लिया था। उन कार्यवाही में, पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि वाहन की अभिरक्षा किराएदार को रुपये की राशि का क्षतिपूर्ति बांड भरने पर दे दी जाए। 80,000 की एक जमानत राशि के साथ और अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि स्वामित्व का प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए। इसी आदेश से परिवाद भी निस्तारित कर दिया गया। उस आदेश का नतीजा यह हुआ कि चोरी का आरोप साबित हुए बिना, आदेश में दर्ज निष्कर्षों को नजरअंदाज करते हुए वाहन का कब्ज़ा किराएदार को दे दिया गया। उस आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। जब उच्च न्यायालय में आगे पुनरीक्षण दायर किया गया, तो वहां भी अपीलकर्ता कंपनी असफल रही। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत में ले जाया गया। अपीलकर्ता कंपनी की अपील की अनुमति देते समय, शीर्ष न्यायालय ने यह कहा: -

“उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करने में सही नहीं किया था और इस तरह उस पक्ष को राहत दी थी जिसने झूठे आरोपों पर अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। अपीलकर्ता ने किराया-खरीद समझौते की शर्तों के तहत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया इस कार्रवाई को अनुबंध द्वारा समर्थित किया जा सकता है, विद्वान मजिस्ट्रेट ने वाहन को केवल क्षतिपूर्ति बांड पर किराए पर लेने वाले को वापस करने का निर्देश दिया। . यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि चोरी के आरोप को पूरा किए बिना ही किराये पर लेने वाले ने राज्य का उपयोग किया साधन, अर्थात्, पुलिस ने वाहन का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया और उसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के माध्यम से उसकी हिरासत प्राप्त कर ली, बिना अपने इस आरोप को पूरा किए कि वह चोरी के कारण वाहन के कब्जे से वंचित था। हम वास्तव में हैं नीचे की अदालतों के दृष्टिकोण पर आश्चर्य हुआ जो पूरी तरह से अस्थिर है। इसलिए, हम विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित और विद्वान सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश दें कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस की मदद से संबंधित वाहन को अपीलकर्ता के कब्जे में वापस कर दिया जाए। यदि अपीलकर्ता द्वारा पुलिस से संपर्क किया जाता है तो वह अपीलकर्ता को वाहन वापस दिलाना सुनिश्चित करेगी। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। यह आदेश पार्टियों के नागरिक अधिकारों, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।”

9)उपर्युक्त मामले में भरोसा किया गया था

सरदार त्रिलोक सिंह के मामले में निर्णय (सुप्रा)। उस स्थिति में,

आरोपी बनाए गए हरबंस सिंह से ट्रक की खरीद को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। ट्रक की खरीद में कुल लागत रु. 60,000. 29 अप्रैल, 1973 को, एक तरफ सत्य देव त्रिपाठी और उनके साथी भगवानी प्रसाद और दूसरी तरफ मेसर्स सरदार फाइनेंस कॉरपोरेशन, कानपुर के बीच एक समझौता हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व अपीलकर्ता नंबर एक ने शीर्ष अदालत में अपने भागीदार के रूप में किया था। . उपरोक्त निगम द्वारा अपनाए गए रुख के अनुसार, उक्त फर्म द्वारा आधा पैसा उन्नत किया गया था जिससे शिकायतकर्ता और उसके साथी को ट्रक हासिल करने में

मदद मिली। शिकायतकर्ता का पक्ष यह था कि उक्त फर्म द्वारा दी गई राशि ऋण के माध्यम से दी गई थी, जबकि शीर्ष अदालत में अपीलकर्ताओं का रुख यह था कि यह पार्टियों के बीच समर्थन में किए गए किराया-खरीद समझौते के आधार पर दिया गया था। जिसका लिखित रूप से औपचारिक समझौता भी निष्पादित किया गया। /शिकायतकर्ता का मामला यह था कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर केवल एक खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। उनका आगे का मामला यह था कि उन्होंने दो मासिक किस्तें चुका दी थीं और तीसरी किस्त जुलाई, 1973 के महीने में देय थी, लेकिन तीसरी किस्त के भुगतान से पहले आरोपी शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में और विरोध के बावजूद शिकायतकर्ता के घर आया। उसकी पत्नी ने हथियारों की धमकी देकर जबरन ट्रक को हटा दिया और इस प्रकार, उन पर धोखाधड़ी के अपराध सहित विभिन्न अपराध करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने नामित आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उपरोक्त निगम द्वारा लिया गया रुख यह था कि पहली किस्त 15 मई, 1973 को, दूसरी 15 जून, 1973 को और तीसरी 15 जुलाई, 1973 को देय थी और इसी तरह। देय संपूर्ण राशि का भुगतान तेईस किश्तों में किया जाना था। किसी भी एक मासिक किस्त के चूक पर फाइनेंसर को बिना किसी सूचना के भी किराया-खरीद समझौते को समाप्त करने और ट्रक को जब्त करने का अधिकार था। चूँकि जुलाई माह की किस्त का भुगतान नियत तिथि तक नहीं किया गया था, शिकायतकर्ता और उसके साझेदारों ने 24 जुलाई, 1973 को ट्रक सरेंडर कर दिया था। संक्षेप में, अपीलकर्ताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत मामला कोर्ट का कहना था कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत बिल्कुल झूठी थी। रिकॉर्ड पर सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अदालत ने यह पाया कि:-

“यह सवाल कि समझौते की शर्तें क्या थीं और क्या उन्हें मुद्रित समझौते में विधिवत शामिल किया गया था या नहीं, ये सभी प्रश्न थे जिनका निर्णय सिविल अदालत में उचित और पर्याप्त रूप से किया जा सकता था। कागजों की खाली शीट पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करना जालसाजी या उसके जैसा कोई अपराध नहीं है। यह तब अपराध बन जाता है जब कागज को इस तरह के दस्तावेज़ में गढ़ा जाता है जो दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित करता है जो इसे अपराध बनाता है या जब ऐसे दस्तावेज़ का उपयोग वास्तविक दस्तावेज़ के रूप में किया जाता है। यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता स्वयं या कुछ अन्य लोगों के साथ गए और 30 जुलाई, 1973 को प्रतिवादी के घर से ट्रक जब्त कर लिया, वे प्रतिवादी द्वारा भुगतान न करने पर ट्रक जब्त करने के अपने वास्तविक अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा करने का दावा कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी था। तीसरी मासिक किस्त समय पर। इसलिए, यह एक वास्तविक नागरिक विवाद था जिसके कारण ट्रक को जब्त कर लिया गया। शिकायत याचिका में ही प्रतिवादी द्वारा दिया गया अत्यधिक अतिरंजित संस्करण, अपीलकर्ता घातक हथियारों से लैस भीड़ के साथ उसके घर गए और ट्रक को छीनने में धोखाधड़ी का अपराध किया, यह इतना अप्राकृतिक और अविश्वसनीय था कि यह हो सकता है मामले को नागरिक विवाद के दायरे से बाहर निकालें. प्रतिवादी पक्ष के किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। किसी को खरोंच तक नहीं आई।”

(10) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय के साथ-साथ मजिस्ट्रेट के आदेशों को रद्द करते हुए अपील की अनुमति दी गई और अपीलकर्ताओं के खिलाफ उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

11) किराया-खरीद समझौते से क्या अधिकार प्रवाहित होता है, चरणजीत सिंह चड्ढा बनाम सुधीर मेहरा में फिर से स्पष्ट रूप से चर्चा की गई, (4) उस मामले में, तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता

व्यापार के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान चला रहे थे -मैसर्स डीलक्स लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम। साझेदारी फर्म के भागीदार, प्रतिवादी, सुधीर मेहरा ने 3 मई, 1994 को अपीलकर्ताओं के साथ किराया-खरीद समझौता किया, जिसके तहत प्रतिवादी को एक मोटर वाहन सौंप दिया गया। प्रतिवादी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल प्रतिफल राशि रु. 3,02,884 और प्रतिवादी ने रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया था। 69,308 और शेष राशि का भुगतान रुपये की 36 मासिक किस्तों में किया जाना था। 3 जून 1994 से शुरू होकर 8,400 प्रत्येक। प्रतिवादी के रुख के अनुसार, वह नियमित रूप से किश्तों का भुगतान कर रहा था। प्रतिवादी ने 3 दिसंबर, 1998 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमृतसर की अदालत में इस आरोप पर एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी कि विचाराधीन मोटर वाहन में कुछ खराबी आ गई थी और इसे मरम्मत करने के लिए 1 सितंबर, 1996 को एक मोटर मैकेनिक को सौंपा गया था। . इसके अलावा, उनके अनुसार, 16 सितंबर, 1996 की रात को अपीलकर्ताओं ने मोटर मैकेनिक से जबरन वाहन छीन लिया और इस प्रकार, आईपीसी की धारा 406/420/120-बी के तहत अपराध किया। मजिस्ट्रेट ने शिकायत में बताए गए अपराध का संज्ञान लिया और अपीलकर्ताओं को समन जारी किया। सम्मन आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने शिकायत कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की थी। अपीलकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया था कि प्रतिवादी ने किस्तों का भुगतान करने में चूक की थी और 1 सितंबर, 1996 तक प्रतिवादी के खिलाफ 1,34,887 रुपये की राशि बकाया थी और इस कारण से, अपीलकर्ताओं को अनुबंध समाप्त करने के लिए बाध्य किया गया था। किराया-खरीद समझौता और प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं को मोटर वाहन सौंप दिया था। इस अदालत के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया और माना कि शिकायत में लगाए गए आरोप विशेष रूप से धारा 379 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध बनाने में सक्षम थे और परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई थी। उस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चले गए। पार्टियों के बीच हुए किराया-खरीद समझौते और मामले के तथ्यों के आधार पर उनके अधिकारों से निपटते हुए, निर्णय के पैरा 5 से 11 में निम्नानुसार कहा गया था: -

5. किराया-खरीद समझौते निष्पादक अनुबंध हैं जिसके तहत सामान किराए पर दिया जाता है और किराएदार के पास समझौते की शर्तों के अनुसार खरीदारी करने का विकल्प होता है। इस प्रकार के समझौते मूल रूप से डीलर और ग्राहक के बीच किए जाते थे और डीलर ग्राहक को ऋण प्रदान करता था। लेकिन जैसे-जैसे कार्यशील पूंजी की उदार मात्रा के साथ किराया-खरीद योजना ने लोकप्रियता हासिल की, इस योजना को मैन कॉस्टर्स तक विस्तारित करना मुश्किल हो गया। फिर फाइनेंसर सामने आए। वित्त कंपनी डीलर से सामान खरीदेगी और किराया-खरीद समझौते के तहत ग्राहक को देगी। डीलर ग्राहक को सामान वितरित करेगा, जो फिर लेन-देन से बाहर हो जाएगा और वित्त कंपनी को ग्राहक से सीधे किश्तें लेने के लिए छोड़ देगा। किराया-खरीद समझौते के तहत, किराये पर लेने वाला केवल सामान के उपयोग और उन्हें खरीदने के विकल्प के लिए भुगतान कर रहा है। वित्त शुल्क, जो नकद मूल्य और किराया-खरीद मूल्य के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, ब्याज नहीं है, बल्कि एक राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे किरायेदार को किश्तों में माल की खरीद मूल्य का भुगतान करने की अनुमति के विशेषाधिकार के लिए भुगतान करना पड़ता है।

6. हालाँकि भारत में संसद ने किराया-खरीद अधिनियम, 1972 पारित कर दिया है, लेकिन इसे अब तक केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई और बाद में उसे वापस ले लिया गया। किराया-खरीद समझौतों से संबंधित नियम उच्च न्यायालयों के निर्णयों द्वारा चित्रित किए जाते हैं। किराया-खरीद समझौते की प्रकृति

की व्याख्या करने वाले इस न्यायालय के कई निर्णय हैं और अधिकतर ये निर्णय तब दिए गए थे जब यह सवाल उठा था कि क्या बिक्री हुई थी ताकि बिक्री कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान आकर्षित किया जा सके।

7. मेसर्स दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1961 एससी 440 में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि बिना अधिक के, केवल काम पर रखने का अनुबंध, जमानत के अनुबंध की एक प्रजाति है, जो शीर्षक नहीं बनाता है जमानतदार, लेकिन किराया-खरीद के कानून में पिछली आधी सदी या उससे अधिक के दौरान काफी विकास हुआ है और इसने कई तरह की शुरुआत की है

विविधताओं के कारण, इस प्रकार श्रेणियां बनती हैं और यह कुछ सूक्ष्मता का प्रश्न बन जाता है कि पार्टियों के बीच कोई विशेष अनुबंध किस श्रेणी में आता है।आम तौर पर, किराया-खरीद का अनुबंध किराएदार को कोई स्वामित्व नहीं देता है, बल्कि कुछ शर्तों को पूरा करने पर खरीदारी करने का एक विकल्प मात्र होता है। लेकिन किराया-खरीद अनुबंध में आस्थगित भुगतान द्वारा किराए पर ली गई वस्तु को खरीदने के समझौते का भी प्रावधान हो सकता है, बशर्ते कि वस्तु का स्वामित्व तब तक पारित नहीं होगा जब तक कि सभी किस्तों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। पार्टियों के बीच सहमत शर्तों के आधार पर किराया-खरीद अनुबंध के अन्य रूप भी हो सकते हैं। जब तीसरे पक्ष में अधिकार पार्टियों के कृत्यों या कानून के संचालन द्वारा बनाए गए हैं, तो सवाल उठ सकता है

मूल अनुबंध के पक्षकारों के वास्तव में क्या अधिकार और दायित्व थे।

8.के.एल. में जौहर एंड कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, एआईआर 1965 एससी-1082, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि किराया-खरीद समझौते में दो तत्व होते हैं; (1) जमानत का तत्व; और (2) बिक्री का तत्व, इस अर्थ में कि यह अंतिम बिक्री पर विचार करता है। बिक्री का तत्व तब फलित होता है जब समझौते की शर्तों को पूरा करने के बाद इच्छुक खरीदार द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जब समझौते की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं और विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो उस सामान की बिक्री होती है जो तब तक किराए पर लिया जा चुका होता है।

9.इसी तरह के विचार पहले किस्त आपूर्ति (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1962 एससी 53 में व्यक्त किए गए थे; और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम केरल राज्य, एआईआर 1966 एससी 1178 में दोहराया गया।

10. इस मामले में पार्टियों द्वारा निष्पादित समझौता इस आशय का है कि किराये पर लेने वाला तब तक संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा जब तक कि वह संपूर्ण भुगतान नहीं कर देता। समझौते की एक प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रथम पक्ष और प्रतिवादी को दूसरे पक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है और यह विशेष रूप से कहा गया है कि पहला पक्ष वाहन का पूर्ण मालिक होगा और प्रतिवादी- दूसरा पक्ष सभी किश्तों का समय पर भुगतान करने पर सहमत हुआ।

समझौते के खंड 7 में कहा गया है कि किराये पर लेने वाला किराया-खरीद समझौते के तहत अंतिम भुगतान देय होने से पहले किसी भी समय और मालिकों को ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में कम से कम चौदह दिन का नोटिस देने के बाद वाहन को फिर से सौंप सकता है। मालिकों को उनके कार्यालय में, किराया-खरीद समझौते को समाप्त करें। खंड 8 (viii) मालिक को वाहन

किराए पर लेने वाले द्वारा चूक की स्थिति में वाहन पर दोबारा कब्ज़ा करने का अधिकार देता है। खंड 9 (ix) मालिक को किसी भी इमारत, परिसर या स्थान में प्रवेश करने के लिए एक अपरिवर्तनीय लाइसेंस देता है जहां वाहन का निरीक्षण, पुनः कब्ज़ा या पुनः कब्ज़ा करने का प्रयास करने के लिए वाहन और वाहन के मालिक को माना जा सकता है। किराये पर लेने वाले के कहने पर किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वाहन को पुनः कब्ज़ा प्राप्त करने या पुनः कब्ज़ा प्राप्त करने का प्रयास करने में मालिक के सभी खर्चों के लिए किराये पर लेने वाला उत्तरदायी होगा।

11. समझौते में शामिल कठोर शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा रखे गए पूरे मामले की सराहना की जानी चाहिए। यदि किराये पर लेने वाले ने स्वयं किस्तों का भुगतान न करके डिफ़ॉल्ट किया है और समझौते के तहत अपीलकर्ताओं ने वाहन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है, तो प्रतिवादी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। प्रतिवादी को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वाहन के मालिक ने वाहन की चोरी या आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश रची है जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है। जब समझौते में विशेष रूप से कहा गया है कि मालिक को वाहन पर दोबारा कब्ज़ा करने का अधिकार है तो यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं हो सकता कि अपीलकर्ताओं ने आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी की है।

12)उपरोक्त प्रकरण में नोटिस भी लिया गया

सरदार त्रिलोक सिंह के मामले में पहले का फैसला (सुप्रा) और के.ए. मथाई और अन्य बनाम कोरा बिब्बिकुट्टी और अन्य (5)। अंतिम विश्लेषण में, यह निर्धारित किया गया था कि कानून में किराया-खरीद समझौता बिक्री का एक निष्पादन अनुबंध है और किराए पर लेने वाले को तब तक कोई अधिकार नहीं देता जब तक कि उसे संपत्ति के हस्तांतरण की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं। इसलिए, समझौते की शर्तों के अनुसार माल का पुनः कब्ज़ा किसी भी आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता है। “चूंकि उस मामले में समझौते ने विशेष रूप से अपीलकर्ताओं को वाहन को फिर से कब्ज़ा करने का अधिकार दिया था और उनके एजेंटों ने कीन को किसी भी संपत्ति या इमारत में प्रवेश करने का अधिकार दिया था जिसमें मोटर वाहन रखे जाने की संभावना थी। इसलिए, किराया-खरीद समझौते के तहत, अपीलकर्ता वाहन के मालिक बने रहे और भले ही उनके खिलाफ सभी आरोपों को सच मान लिया जाए, उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया। नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और शिकायत और ऐसी शिकायत के अनुसार शुरू की गई अन्य कार्यवाही रद्द कर दी गई।

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि वाहन के किराएदार रमेश कुमार द्वारा धरमिंदर और सात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सत्र न्यायाधीश, भिवानी के 23 दिसंबर, 2000 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन वाहन को पंजीकृत मालिक से कब्जे में ले लिया गया था और राजेंद्र प्रसाद के मामले (सुप्रा) में आदेश का पालन करते हुए वाहन को रिहा करने का आदेश दिया गया था। उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी के 7 जून, 2000 के आदेश को रद्द करते हुए, पंजीकृत मालिक अर्थात् रमेश कुमार। राजेंद्र प्रसाद के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि विवाद में वाहन के स्वामित्व से संबंधित प्रश्न और वाहन से संबंधित लेनदेन के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करणों की शुद्धता पर निर्णय नहीं लिया गया था। वाहन को गर्मी और ठंड के संपर्क में आने से बचाने के लिए, वाहन को अस्थायी रूप से अपीलकर्ता राजेंद्र प्रसाद को सौंपने का आदेश दिया गया था, जो पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रत्यक्ष धारक था।

यह भी निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता के पास मौजूद वाहन की अभिरक्षा अदालत की ओर से होगी और उक्त व्यवस्था केवल उस चरण तक थी जब अदालत ने मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटान के संबंध में आदेश पारित किया था।

14) उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रश्न में वाहन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किराया-खरीद समझौते के तहत प्राप्त किया गया था या लेनदेन की शर्तें क्या थीं जिसके तहत वह वाहन के मालिक बन गए। इस प्रकार, यह निर्णय किसी भी तरह से मामले की परिस्थितियों में प्रतिवादी की मदद नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के रुख के अनुसार, वर्तमान मामले में विवाद यह है कि प्रतिवादी रमेश कुमार को वाहन पर कब्ज़ा करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को ख़त्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि किराया-खरीद समझौते की शर्तों के तहत उसने किश्तों की राशि के भुगतान में चूक की गई, जैसा कि 27 फरवरी, 1998 के किराया-खरीद समझौते की शर्तों से स्पष्ट है, जो याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए समझौते के साथ संलग्न पहली और दूसरी अनुसूची में विस्तृत भुगतान की अनुसूची के साथ जुड़ा हुआ है। . यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने छोटू राम को रमेश कुमार से वाहन वापस लेने के लिए अधिकृत किया था और 19 मई, 2000 के प्राधिकार पत्र की प्रति लगाई गई थी।
रिकॉर्ड पर।
(15) इस स्तर पर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों पर ध्यान देना होगा, जिसमें "मालिक" शब्द है
वह व्यक्ति जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत किया गया है
और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का संरक्षक और मोटर वाहन के संबंध में जो किराया-खरीद समझौते या पट्टे के समझौते या दृष्टिबंधक समझौते का विषय-वस्तु है, उस समझौते के तहत वाहन के कब्जे में व्यक्ति। उपर्युक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि "मालिक" शब्द को अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक विस्तारित और व्यापक अर्थ दिया गया है क्योंकि यह एक व्यक्ति बनाता है, जिसके पास कब्ज़ा है
प्रश्नगत वाहन जो कि किराया-खरीद समझौते का विषय-वस्तु है, अधिनियम के प्रयोजन के लिए मालिक भी है। इन प्रावधानों का शुद्ध परिणाम यह होगा कि किराया-खरीद समझौता होने के बावजूद, किराया-खरीद समझौते के तहत कब्जा रखने वाला व्यक्ति इसके तहत आवेदन दायर करने का हकदार होगा।
अधिनियम की धारा 41 ताकि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकृत मालिक के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में सक्षम हो सके। सक्षम करने का उद्देश्य 1988 के अधिनियम के तहत ये प्रावधान किराएदार को मान्यता देते प्रतीत होते हैं
एक मालिक के रूप में न केवल वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र को बनाए रखना है, जो किराया-खरीद समझौते का विषय-वस्तु है, बल्कि उसे फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने, वाहन का बीमा करवाने, रूट परमिट आदि आवश्यक करने में भी मदद करता है। जिसका अनुपालन 1988 अधिनियम के तहत किया जाना आवश्यक है ताकि वाहन को किसी भी ओर से बिना किसी बाधा के चलाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता
इसका मतलब यह है कि वह पूर्ण मालिक बन जाता है क्योंकि किराया-खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार, किराएदार को शर्तों को पूरा करना होता है इसमें निर्धारित किया गया है और किस्तों की राशि का भुगतान करना होगा ताकि किराया-खरीद समझौते के संदर्भ में पूर्ण मालिक बन सकें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 अदालत को जांच या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति की हिरासत और निपटान के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार देती है और जिस संपत्ति के संबंध में अपराध किया गया प्रतीत होता है या अपराध करने के लिए उपयोग किया

गया प्रतीत होता है। . इस मामले में, वाहन की कस्टडी के लिए किरायेदार रमेश कुमार और फाइनेंसर द्वारा दावा किया गया था-

याचिकाकर्ता, मजिस्ट्रेट किराया-खरीद समझौते की शर्तों की जांच करने के लिए बाध्य था क्योंकि फाइनेंसर द्वारा एक निश्चित रुख अपनाया गया था कि किस्त राशि के भुगतान में चूक किराएदार द्वारा की गई है और केवल इसलिए कि पंजीकरण प्रमाणपत्र किराएदार के नाम पर जारी किया गया, जो , जो वैसे वाहन का हक़दार ना बनता लेकिन इस किरायदार समझौते से बना प्किसी भी तरह से अंतरिम प्राप्त करने के लिए किराया-खरीद समझौते के तहत फाइनेंसर के अधिकार को नहीं छीनेगा। विचाराधीन वाहन की अभिरक्षा क्योंकि उस समय तक किराये पर लेने वाला संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं बन गया था। सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से विचार किया है कि प्रश्न में वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में, यह भी उल्लेख किया गया था कि इसे याचिकाकर्ता-फाइनेंसर और किराया-खरीद के तहत वाहन के पूर्ण मालिक के पास गिरवी रखा गया है। समझौते के अनुसार फाइनेंसर को किराएदार द्वारा किए गए डिफ़ॉल्ट के कारण वाहन पर कब्ज़ा करने का अधिकार था। इन सभी परिस्थितियों पर सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, उन्होंने आदेश में कुछ भी नहीं कहा है कि किस आधार पर उन्होंने पाया कि उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुपरदारी पर विचाराधीन वाहन को छोड़ने का आदेश देने में गलती की है। फाइनेंसर को.

(16) उपरोक्त कारणों से, सत्र न्यायाधीश, भिवानी के आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 2000 के अनुसार पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है।

कानून में अस्थिर होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है और उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की दिनांक 7 जून, 2000 को बहाल कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा